

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फ़रीदाबाद 1
वीहरियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

(पूर्ण बेंच)

पहले: एपी चौधरी, जवाहर लाल गुप्ता और एनके सोढ़ी, जे जे।

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फ़रीदाबाद, -
याचिकाकर्ता।

बनाम

■ हरियाणा राज्य और अन्य, -प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 1989 का 10277.

22 जनवरी, 1993.

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956—एस. 3—हरियाणा सामान्य बिक्री-कर अधिनियम, 1973 जैसा कि अधिनियम, 1989 द्वारा संशोधित—एस.एस. 2(पीए), 2(1) नोट 3, 2(जे), 12 प्रविष्टि 14 और अनुसूची 'बी' की 52 - भारत का संविधान, 1950 कला। 269, 286 और 366 सीएल। संविधान का 29-ए (छियालीसवों संशोधन) अधिनियम, 1982 - कार्य अनुबंध - बिक्री और खरीद की संशोधित परिभाषा - ऐसी बिक्री इंटर स्टेट बिक्री तक ही सीमित है - उपधारा 1 का नोट 3 राज्य विधानमंडल के अंतर्गत है - 'की व्यापक परिभाषा कार्य अनुबंध इसे राज्य विधानमंडल की शक्तियों के दायरे से बाहर नहीं करेगा - संशोधन अधिनियम की धारा 2 संवैधानिक रूप से वैध है - सीएल। कला के 29-ए. 366 एक सक्षम प्रावधान है - स्थानीय अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन के अभाव में कर अधिकारी उन लेनदेन पर केंद्रीय अधिनियम के तहत कर नहीं लगा सकते हैं जो केंद्रीय अधिनियम की धारा 2 (जी) के अनुसार बिक्री के बराबर नहीं हैं।

आयोजित, नोट 3 राज्य विधानमंडल की शक्तियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। इस स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि नोट 3 में 'बिक्री' शब्द केवल अंतर-राज्य बिक्री तक ही सीमित है, हम नोट 3 को केवल अंतर-राज्य बिक्री तक ही सीमित रखेंगे। 'कार्य अनुबंध' की परिभाषा को केवल इसलिए संविधान या राज्य विधानमंडल की शक्तियों के दायरे से बाहर नहीं

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद 2
वीहरीयाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

रखा गया है क्योंकि यह व्यापक संदर्भ में है।

(पैरा 24, 25 एवं 27)

आयोजित, यदि लॉटरी टिकटों को लॉटरी टिकटों के रूप में बेचा जाना है, तो जब तक वर्तमान प्रावधान जारी रहेंगे तब तक बिक्री कर लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। वस्त्रों के मामले में भी यही सच है। सवाल उठता है कि क्या जिस चीज पर कर लगाने की मांग की गई है वह लॉटरी टिकट के रूप में लॉटरी टिकट है या कपड़ा के रूप में कपड़ा। हमारी नजर में ऐसा नहीं है। जिस चीज पर कर लगाने की मांग की गई है वह एस 2 के खंड (1) के खंड (ii) के संदर्भ में कार्य अनुबंध के निष्पादन में माल में संपत्ति का हस्तांतरण है। इसमें कागज आदि शामिल होंगे जिनका उपयोग लॉटरी टिकट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसी तरह एल.वी. वस्त्रों के मामले में, जिस पर कर लगाने की मांग की गई है वह वह सामान है जो एस. 2 के खंड (1) के उक्त उपखंड (ii) और अन्य के दायरे में आएगा। हम नहीं कर रहे हैं

इस प्रश्न पर विचार करने की सलाह दी जाती है कि किस वस्तु के संबंध में संपत्ति, खंड (ii) के संदर्भ में अनुबंधकर्ता के पक्ष में जाती है और किसमें नहीं। चीजों की प्रकृति में, यह निर्धारित करने के लिए कर अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या विचाराधीन सामान बिक्री कर लगाने के प्रयोजनों के लिए खंड (ii) के तहत कवर (पैरा 27 एवं 29) किया गया है या नहीं।

आयोजित, कि 1989 के हरियाणा संशोधन अधिनियम संख्या 1 द्वारा संशोधित धारा 2 के प्रावधानों को संवैधानिक रूप से वैध माना जाना चाहिए। (पैरा 30)

आयोजित, इसलिए, कपड़े की आवाजाही, एचजीएसटी अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (1) के उप-खंड (ii) के अर्थ के भीतर बिक्री के अनुबंध द्वारा होती है। इसलिए, हमारा विचार है कि उक्त लेनदेन केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अर्थ के अंतर्गत एक अंतर-राज्यीय बिक्री के बराबर है। (पैरा 32)

आगे आयोजित, यदि कर केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम के तहत लगाया जाना है, तो कर अधिकारी केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों से आगे नहीं बढ़ सकते। कला में खंड (29-ए) का सम्मिलन। 366 में संविधान के विभिन्न प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए "बिक्री और खरीद पर कर" अभिव्यक्ति की केवल विस्तारित परिभाषा शामिल है। यह संसद को 'बिक्री' शब्द सहित केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम में प्रयुक्त प्रासंगिक अभिव्यक्तियों की परिभाषा में उपयुक्त संशोधन करने के लिए एक सक्षम प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है यदि इसका उद्देश्य खंडों में विभिन्न लेनदेन के संबंध में बिक्री कर लगाना है (ए) अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के (जे) तक, मोटे तौर पर उन तर्ज पर जिन पर विभिन्न राज्यों ने स्थानीय सामान्य बिक्री-कर अधिनियमों में संशोधन किया है। चूंकि ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 के तहत उन लेनदेन पर बिक्री-कर लगाने के लिए आगे बढ़ना कर अधिकारियों के लिए खुला नहीं है, जो एस. 2 (जी) में परिभाषित बिक्री के बराबर नहीं हैं। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956.

(पैरा 33)

आयोजित इसके अलावा, एचजीएसटी अधिनियम, 1973 की धारा 2 के (1)

खंड (जे) और (1), जिसमें एचजीएसटी अधिनियम, 1973 के नोट 2, नोट 3 के प्रावधान भी शामिल हैं, संविधान और इसमें तैयार किए गए सिद्धांतों के अंतर्गत हैं। संविधान के अनुच्छेद 269(3) और 286(2) के अनुसरण में केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956। उस सीमा तक 1989 के अधिनियम संख्या 1 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी जाती है।

(2) एचजीएसटी अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (जे) और (1) के विभिन्न उप-खंडों के दायरे में आने वाले माल का मूल्य कर के दायरे में आता है।

(3) कर लगाने के उद्देश्य से अंतरराज्यीय बिक्री एचजीएसटी अधिनियम, 1973 के दायरे से बाहर है।

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद 3
वीहरियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

(4) ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा भूरे कपड़े को तैयार कपड़े में बदलने की विशेष गतिविधि तथ्यों और परिस्थितियों में अंतर-राज्यीय बिक्री के बराबर है।

(5) कर निर्धारण अधिकारियों के लिए यह खुला है कि वे समग्र कार्य अनुबंध को विभाजित कर सकते हैं और अनुबंध के उस घटक पर कर लगा सकते हैं जो धारा 2 के खंड (जे) या खंड (1) के एक या अन्य उप-खंडों द्वारा कवर किया गया है। एचजीएसटी अधिनियम, 1973।

(6) संविधान (छियालीसवें) संशोधन अधिनियम, 1982 द्वारा अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) में बिक्री या खरीद पर अभिव्यक्ति कर की व्यापक परिभाषा के बावजूद, कर केवल केंद्र के मौजूदा प्रावधानों के आधार पर लगाया जा सकता है। बिक्री-कर अधिनियम, 1956, न कि अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के विभिन्न उप-खंडों के आधार पर, जहां तक केंद्रीय बिक्री-कर का संबंध है।

(7) कर निर्धारण प्राधिकारी एचजीएसटी अधिनियम, 1973 के खंड (जे) के उप-खंड (ii) या धारा 2 के खंड (1) के संदर्भ में तथ्यों और तथ्यों में यह निर्धारित करेंगे कि कौन से सामान, संपत्ति अनुबंधकर्ता को मिलती है। प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ।

(8) जब सवाल उठाया जाता है, तो कर अधिकारियों को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह निर्धारित करना होता है कि लेनदेन राज्य के भीतर बिक्री है या अंतर-राज्य बिक्री है।

(9) एसएस के तहत बिक्री-कर से छूट (शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, उसमें उल्लिखित)। एचजीएसटी अधिनियम, 1973 की अनुसूची 'बी' के साथ पठित धारा 6 और 15 ऐसे माल के रूप में माल के संदर्भ में हैं। यदि कोई मामला किसी भी उप-खंड में आता है तो छूट लागू नहीं होती है खंड (ii) का.

(पैरा 34)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका प्रार्थना है कि:-

- (a) यह माननीय न्यायालय एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा कर सकता है ताकि यह घोषित किया जा सके कि धारा में संशोधन 1989 के हरियाणा अधिनियम संख्या 1 में किए गए 2, जिन्हें हरियाणा सामान्य बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम,

1989 कहा जाता है, भारत के संविधान के अधिकारातीत हैं और इन्हें कानून की किताब से हटाने का निर्देश दिया जा सकता है:

- (b) *वह प्रतिवादी सं०२* को उचित रिट, आदेश या निर्देश के माध्यम से निर्देशित किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा 18 अप्रैल, 1984 से आज तक की गई खरीद या निष्पादन के संबंध में कच्चे माल पर कर लगाने के लिए मूल्यांकन की समीक्षा करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई न करें। याचिकाकर्ता कंपनी के उपयोग के लिए कपड़े के निर्माण के लिए याचिकाकर्ता द्वारा अंतर-राज्यीय बिक्री और/या खरीद के लिए कार्य अनुबंध:
- (c) *द. प्रतिवादी संख्या* द्वारा शुरू की गई कार्यवाही² को रद्द किया जा सकता है:
- (d) *मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए और संलग्न विविध आवेदन में मांगी गई राहत की तत्काल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, याचिका दायर करने से पहले उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस देने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है:*
- (e) *याचिकाकर्ता को ऐसी अन्य उचित राहत दी जा सकती है जिसे माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे और याचिका को लागत के साथ स्वीकार किया जा सकता है। तदनुसार प्रार्थना की जाती है।*

याचिकाकर्ता के लिए एसएस चड्ढा, वकील और एसएस वालिया, वकील।

एचएल सिब्बल, एजी (हरियाणा) और आरसी सेतिया, अतिरिक्त।
उत्तरदाताओं के लिए एजी (हरियाणा) और एसएस खेत्रपाल, डीए,
(हरियाणा)।

आदेश

एपी चौधरी, जे.

इन रिट याचिकाओं में (संख्या 5691, 7317, 9565, 9564, 10277, 13602 और 1989 की 13842, 1990 की 5393 और 9022 और 337, 1331, 1501, 3764, 3984, 4696 से 4698, 9) 1992 के 455 और 16812 और 16813 1991) मुख्य जीवित चुनौती हरियाणा सामान्य बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम (हरियाणा

अधिनियम संख्या 1) द्वारा हरियाणा सामान्य बिक्री-कर अधिनियम, 1973 (संक्षेप में, एचजीएसटी अधिनियम) की धारा 2 में किए गए कुछ संशोधनों को लेकर है। ओटी 1989) (संक्षेप में, संशोधन अधिनियम 1989 है;। ये याचिकाएँ इस न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं। विद्वान न्यायाधीशों ने देखा कि 1989 के संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न महान में से एक था। सार्वजनिक महत्व और तदनुसार 3 जून, 1992 के आदेश द्वारा इसे पूर्ण पीठ को भेज दिया गया। इस तरह ये याचिकाएँ हमारे सामने हैं।

(2) तथ्यात्मक पृष्ठभूमि बताने के लिए इन याचिकाओं को अलग-अलग सेटों में समूहित करना सुविधाजनक होगा।

(3) सीडब्ल्यूपी नंबर 5691, 9565, 9564, 10277, 13602 और 1989 के 13812, 1990 के 5393 और 9022 और 1331, 1992 के 1501 और 16812 और 1991 के 16813 के पहले सेट में, सीडब्ल्यूपी नंबर 1 में तथ्य 1989 के 0277 हैं काफी प्रतिनिधिक और संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है: -

याचिकाकर्ताकी अपनी फैक्टरी है और यह हरियाणा राज्य के फ़रीदाबाद में काम करती है। यह दोनों के अंतर्गत एक पंजीकृत डीलर है

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फ़रीदाबाद 113
हरियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

एचजीएसटी अधिनियम के साथ-साथ केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956। यह विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण और प्रसंस्करण में लगा हुआ है। इसमें जिसे ग्रे कपड़ा कहा जाता है उसे तैयार कपड़े में बदलना शामिल है। भूरे कपड़े को विभिन्न उपचारों और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जिसमें ब्लीचिंग एजेंटों और कई रसायनों का उपयोग शामिल होता है। इसके बाद ठेकेदार के आदेश के अनुसार कपड़े की रंगाई, आकार और छपाई की जाती है। किसी भी रंगाई/छपाई आदि के प्रसंस्करण में प्रयुक्त सामग्री याचिकाकर्ता द्वारा 'सी' फॉर्म में घोषणा प्रस्तुत करने पर राज्य के बाहर से खरीदी जाती है। याचिकाकर्ता रिटर्न जमा कर रहा था और देय बिक्री-कर की राशि का भुगतान कर रहा था। उप उत्पाद एवं कराधान आयोग। (निरीक्षण) फ़रीदाबाद ने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एचजीएसटी अधिनियम की धारा 40(2) के तहत याचिकाकर्ता को नोटिस अनुलग्नक पी-4 और पी-5 जारी किए। ये नोटिस क्रमशः आकलन वर्ष 1984-85 और 1985-86 से संबंधित हैं। अनुलग्नक पी-4 में, अन्य बातों के अलावा, यह कहा गया था कि 30 जून, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए बैलेंस शीट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने प्रसंस्करण और आकार शुल्क के रूप में रु. का शुल्क लिया था। 4,31,87,383.37 पैसे। आगे यह कहा गया कि उक्त कार्य अनुबंध के निष्पादन में, याचिकाकर्ता ने रुपये की सामग्री का उपभोग किया था। एचजीएसटी अधिनियम के साथ-साथ केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 के तहत समान खरीदने के बाद 4,27,06,216.79। याचिकाकर्ता को यह बताने के लिए बुलाया गया था कि उक्त वर्ष के लिए मूल्यांकन फिर से क्यों नहीं खोला जाए और बिक्री कर क्यों नहीं लगाया जाए। कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं की कीमत पर। नोटिस अनुबंध पी-5, नोटिस अनुबंध पी-4 के समान शर्तों में है, सिवाय इसके कि यह मूल्यांकन वर्ष 1985-86 से संबंधित है और इसमें शामिल राशि भी अलग है। चूंकि विचाराधीन नोटिस हरियाणा संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा संशोधित एचजीएसटी अधिनियम की धारा 2 के खंड (1) (ii) के संशोधित प्रावधानों पर आधारित थे, इसलिए याचिकाकर्ता ने नोटिस के साथ-साथ कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है। हरियाणा संशोधन अधिनियम 1989 का।

(5) सीडब्ल्यूपी के दूसरे सेट (संख्या 337, 3764, 3984, 4696, 4697 और 1992 के 4698) में हम 1992 के सीडब्ल्यूपी संख्या 4697 से तथ्यों को बता सकते हैं।

(6) याचिकाकर्ता पुस्तकों, बहुरंगी पत्रिकाओं, राजनयिक पत्रिकाओं, कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट, ब्रोशर, फ़ोल्डर्स आदि और लॉटरी टिकटों की छपाई में लगा हुआ है। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कार्य में अत्यधिक उन्नत तकनीक, परिष्कृत मशीनरी और उच्च योग्य और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण हिस्सा गोपनीयता की उच्च डिग्री है

हवा; याचिकाकर्ता को अपने ऑर्डर देने वाले विभिन्न पक्षों की संतुष्टि को बनाए रखना आवश्यक है, खासकर लॉटरी टिकटों की छपाई के मामले में। ऑर्डर देने वाली पार्टियाँ कभी-कभी मुद्रण के लिए अपना स्वयं का कागज उपलब्ध कराती हैं। अन्य अवसरों पर याचिकाकर्ता आदेश को पूरा करने के लिए अपने स्टॉक से कागज का उपयोग करता है। याचिकाकर्ता एचजीएसटी अधिनियम के साथ-साथ केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत एक पंजीकृत डीलर है। लॉटरी टिकटों को हरियाणा अधिनियम के तहत बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई है। याचिकाकर्ता नियमित रूप से बिक्री कर रिटर्न दाखिल कर रहा था और समय-समय पर मूल्यांकन के अनुसार कर का भुगतान कर रहा था। याचिकाकर्ता ने लॉटरी टिकटों को बिक्री-कर से मुक्त होने के कारण एक निश्चित राशि की कटौती का दावा किया। इसकी अनुमति दी गई और मूल्यांकन तैयार किया गया, - 30 जनवरी, 1990 के अनुबंध पी-2 के माध्यम से। पुनरीक्षण प्राधिकारी-सह-उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (निरीक्षक) फरीदाबाद (पूर्व) ने 24 अप्रैल को अनुबंध पी-1 जारी किया। , 1992, याचिकाकर्ता को निर्धारण वर्ष 1984-85 के निरीक्षण रिकॉर्ड के आधार पर एचजीएसटी अधिनियम/केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम की धारा 40(2) के तहत। यह बताया गया कि उक्त मूल्यांकन आदेश में लॉटरी टिकट के रूप में उपयोग के लिए मुद्रित सामग्री की बिक्री रु। मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा 6,15,41,998 रुपये को लॉटरी टिकट मानकर कर मुक्त माल की बिक्री के रूप में मूल्यांकन किया गया था। नोटिस में आगे कहा गया है कि मुद्रित सामग्री

की बिक्री लॉटरी टिकटों की बिक्री के बराबर नहीं है क्योंकि जो बेचा गया था वह लॉटरी टिकटों के रूप में कागज की मुद्रित पर्चियां थीं न कि लॉटरी टिकट। उच्चतम न्यायालय एच. अनराज बनाम तमिलनाडु सरकार (1) के फैसले का संदर्भ दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि लॉटरी टिकट खरीदने वाले को दो अधिकार प्रदान किए जाते हैं, अर्थात्, ड्रा में भाग लेने का अधिकार, और दूसरा। , बीईएमजी द्वारा विजेता घोषित किए जाने पर पुरस्कार का दावा करने का अधिकार। चूंकि मुद्रित सामग्री की बिक्री क्रेता को इनमें से कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करती, इसलिए बिक्री को लॉटरी टिकटों की बिक्री नहीं माना जा सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता को यह बताने के लिए बुलाया गया था कि मूल्यांकन आदेश को क्यों रद्द कर दिया गया और ऊपर उल्लिखित आइटम को मंच में शामिल नहीं किया गया है? हरियाणा संशोधन अधिनियम के 80 निश्चित प्रावधानों के समान 1[^] की वैधता

„फल?।सीडब्ल्यूपी का तीसरा सेट ^ 1989 का 7317 और 1989 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7317 में 9544 तथ्य बताए जा सकते हैं।

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद 7
वीहरियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

(8) याचिकाकर्ता ठेकेदारी का व्यवसाय करता है। याचिकाकर्ता ने हरियाणा राज्य में ठेकेदार के रूप में निर्माण कार्य किया। स्टील और सीमेंट सहित सामग्री की आपूर्ति अनुबंधित सरकारी विभागों द्वारा की गई थी। याचिकाकर्ता को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा एचजीएसटी अधिनियम की धारा 29 के तहत एक नोटिस दिया गया था कि याचिकाकर्ता अप्रैल, 1988 से 23 जनवरी तक की अवधि के संबंध में एचजीएसटी अधिनियम के तहत बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। 1989. पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहने पर याचिकाकर्ता जुर्माने के अलावा कर निर्धारण के लिए भी उत्तरदायी हो गया। इसलिए, याचिकाकर्ता को जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने के अलावा यह पूछने के लिए कहा गया कि इसके खिलाफ सर्वोत्तम निर्णय क्यों नहीं दिया जाए। जवाब में, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर किसी भी बिक्री कर का भुगतान करने के अपने दायित्व से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता के पास जो कुछ था वह पूरी तरह से जॉब-वर्क था। मुख्य सामग्री, अर्थात् 'स्टील' और 'सीमेंट' की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा की गई थी। ; शेष कार्य बिक्री-कर के दायरे में नहीं आता था।

(9) 1989 के सीडब्ल्यूपी नंबर 13602 में याचिकाकर्ता जॉब वर्क के आधार पर माल के प्रसंस्करण/विनिर्माण में लगा हुआ है। पुनरीक्षण प्राधिकारी-सह-उप उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त (निरीक्षण) फरीदाबाद ने रिकॉर्ड के निरीक्षण के आधार पर याचिकाकर्ता को मूल्यांकन वर्ष 1986-87 के लिए नोटिस एनहेक्सर पी-2 जारी किया। यह नोटिस भी प्रासंगिक अवधि के लिए बैलेंस शीट पर आधारित है और इसमें उल्लिखित मूल्यांकन को फिर से खोलने का आधार यह है कि याचिकाकर्ता ने कार्य अनुबंध निष्पादित किया था जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि की सीमा तक संपत्ति और माल पारित किया गया था। ठेकेदार के पक्ष में उक्त राशि को "बिक्री" की संशोधित परिभाषा के तहत शामिल करते हुए, याचिकाकर्ता को जुर्माना लगाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के अलावा, कारण बताने के लिए कहा गया था कि मूल्यांकन को संशोधित क्यों नहीं किया जाए।

(10) तथ्यों के उपरोक्त संक्षिप्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद 8
वीह्रियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

इन रिट याचिकाओं के पक्षकारों के बीच मुख्य विवाद मुख्य अधिनियम के 1989 के संशोधन अधिनियम 2 द्वारा किए गए कुछ संशोधनों के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

(11) शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि कुछ रिट याचिकाओं में, संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982 की शक्तियों को चुनौती दी गई है। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, आदि (2) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर चुनौती को निरस्त किया जाना चाहिए।

(2) एआईआर, 1989 एससी 1371।

(12) याचिकाकर्ता की ओर से मिटाए गए विवादों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है: -

- (i) नोट 8 में हरियाणा संशोधन अधिनियम 1989 की परिभाषा या 'खरीद' और 'बिक्री' शब्दों के तहत क्रमशः खंड (2) (जे) और 2(1) में एक कानूनी गुट पेश किया गया है जो कि "बिक्री 1" गिर रहा है। यदि कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल सामान कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग के समय राज्य के भीतर हैं, तो संबंधित खंड के उप-खंड (ii) के तहत राज्य के भीतर हुआ माना जाएगा। 'बिक्री' शब्द को अंतर-राज्य बिक्री तक सीमित करने वाले किसी भी शब्द के अभाव में, 'बिक्री' शब्द में अंतर-राज्य बिक्री भी शामिल होगी। यदि नोट का ऐसा अर्थ लगाया जाता है, तो यह अंतर-राज्यीय बिक्री को एचजीएसटी, अधिनियम, 1973 के दायरे में लाएगा। यह अधिनियम को राज्य विधानमंडल के संविधान और शक्तियों के दायरे से बाहर कर देगा।
 - (ii) अभिव्यक्ति "कार्य अनुबंध" (जो संविधान के अनुच्छेद 366 में परिभाषित नहीं है) को हरियाणा संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 2(पीए) में इतने व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया है कि इसमें शामिल होगा:
 - (a) लेन-देन जो पूरी तरह से नौकरी का काम है, कार्य अनुबंध से अलग है जिसमें माल का उपयोग शामिल है जिसके संबंध में माल में संपत्ति अनुबंधकर्ता को मिलती है।
 - (b) इस परिभाषा में ऐसे सामान भी शामिल हैं जो पूरी तरह या लगभग पूरी तरह उपभोग या खर्च हो चुके हैं।
- जोर इस बात पर दिया गया है कि खंड (ii) के दायरे में आने के लिए सामान को सामान ही रहना चाहिए चाहे वह उस रूप में हो या किसी अन्य रूप में।
- (iii) कपड़ा और लॉटरी को बिक्री-कर से छूट दी गई है, - हरियाणा सामान्य बिक्री-कर अधिनियम, 1973 की अनुसूची 'बी' की व्यापक प्रविष्टि 14 और प्रविष्टि 52। इसलिए, याचिकाकर्ता उन वस्तुओं पर किसी भी बिक्री-कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। . यह तर्क दिया गया कि यह असंगत होगा यदि समझी गई बिक्री बिक्री-कर के अधीन है, जबकि उचित रूप से तथाकथित बिक्री बिक्री-कर लगाने से मुक्त है।
 - (iv) यह राज्य विधानमंडल के लिए उप-खंड (ii) और उप-खंड (iv) के कुछ हिस्सों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए खुला नहीं है, जिसका प्रभाव निर्धारिती को 18 अप्रैल की अवधि के लिए पूर्वव्यापी रूप से बिक्री कर का भुगतान करने के लिए

उत्तरदायी बनाना था। 1984 से 31 मार्च, 1987 तक।

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद 9
वीह्रियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

(v) इन याचिकाओं के विभिन्न सेटों में याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य में परिष्कृत प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकी शामिल हैं जो केवल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण से अलग हैं। लॉटरी टिकटों की छपाई के मामले में उच्च स्तर की गोपनीयता की आवश्यकता होती है। ये नौकरी के काम थे और बिक्री-कर के दायरे में नहीं आते थे।

(vi) लॉटरी टिकटों की छपाई के मामले में याचिकाकर्ता प्रिंटिंग प्रेस द्वारा कागज की आपूर्ति केवल आकस्मिक थी और उस पर बिक्री कर नहीं लगता था।

(vii) 1989 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10277 सहित सीडब्ल्यूपी के पहले सेट में, जिसमें से पैराग्राफ 4 में तथ्यों को निर्धारित किया गया था, आगे का तर्क यह है कि यह मानते हुए कि निर्धारिती की गतिविधि कार्य अनुबंध के निष्पादन के बराबर है और आगे यह मानते हुए कि माल में संपत्ति का हस्तांतरण धारा 2 के खंड (1) के उप-खंड (ii) के अर्थ के भीतर ऐसे कार्य अनुबंध के निष्पादन में होता है, लेनदेन एक अंतर-राज्यीय बिक्री थी और इसलिए, राज्य बिक्री-कर के लिए योग्य नहीं थी।

(13) विभिन्न तर्कों पर हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता श्री एचएल सिब्बल द्वारा दिए गए उत्तर को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: -

(i) नोट 3 में प्रयुक्त शब्द "बिक्री" केवल अंतर-राज्य बिक्री तक ही सीमित है। इसे अंतरराज्यीय बिक्री शामिल नहीं माना जा सकता। यहां तक कि अंतर-राज्य बिक्री से भी, नोट 3 में उल्लिखित बिक्री केवल खंड (1) के उप-खंड (ii) के अंतर्गत आने वाली बिक्री तक ही सीमित है। यह बताया गया कि धारा 12 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि एचजीएसटी अधिनियम, 1973 में कुछ भी अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली बिक्री या खरीद पर कर

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद 10
वैहरियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

लगाने का अधिकार नहीं देगा।

- (ii) कर लगाने की घटना खंड (1) के उप-खंड (i) से (v) के अर्थ के भीतर किसी भी सामान का स्थानांतरण, वितरण या आपूर्ति है, न कि अभिव्यक्ति "कार्य अनुबंध" की व्यापक परिभाषा। इसलिए, इसका कोई परिणाम नहीं था कि अभिव्यक्ति "कार्य अनुबंध" को यथासंभव व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया था।
- (iii) कपड़ा और लॉटरी को बिक्री-कर से छूट, - एचजीएसटी अधिनियम की अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि 52 के तहत केवल में है

उनकी बिक्री या खरीद का सम्मान. दूसरे शब्दों में, यदि खंड (1) के उप-खंड (ii) के दायरे में आने वाले कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान माल का हस्तांतरण अनुबंधकर्ता के पक्ष में होता है, तो लेनदेन को छूट नहीं माना जा सकता है .

(iv) यह सुस्थापित कानून है कि विधायिका पूर्वव्यापी प्रभाव दे सकती है। वर्तमान मामले में, यह बताया गया था, सरकार को रिपोर्ट मिली थी कि संबंधित डीलरों ने वास्तव में, अवधि के दौरान उप-खंड (1) के नोट-2 के प्रावधान के दायरे में आने वाले बिक्री कर का आरोप लगाया था। 18 अप्रैल, 1984 से 1 अप्रैल, 1987 तक। डीलरों को पहले से एकत्र की गई राशि को अपने पास रखने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं था। बिक्री-कर और अन्यायपूर्ण संवर्धन को रोकने के लिए, नोट 2 के तहत खंड (1) में परंतुक और नोट 2 के तहत खंड (जे) में एक समान प्रावधान डालकर पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। डीलर द्वारा वास्तव में वसूले गए कर की सीमा तक दावे पर एक सीमा तय करने का ध्यान रखा गया था।

(v) और (vi) संविधान के छियालीसवें संशोधन से पहले कुछ कार्य अनुबंधों को संपूर्ण और अविभाज्य माना जाता था। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मामले (सुप्रा) में यह शीर्ष न्यायालय द्वारा माना गया था कि छियालीसवें संशोधन के बाद, कार्य अनुबंध, जो एक अविभाज्य था, कानूनी रूप से एक अनुबंध में बदल दिया गया है जो बिक्री के लिए एक में विभाजित है सामान और अन्य श्रम और सेवाओं की आपूर्ति के लिए, - (पेज 1390 पर पैराग्राफ 36 के अनुसार)।

(vii) श्री सिब्बल ने आगे तर्क दिया कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए इसे एचजीएसटी अधिनियम के तहत कर अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए:

(a) क्या माल में संपत्ति खंड (1) के उप-खंड (ii) के अर्थ के भीतर कुछ वस्तुओं के संबंध में पारित हुई है; और

(b) क्या लेनदेन अंतर-राज्य बिक्री थी या अंतर-राज्य बिक्री।

श्री सिब्बल ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि न्यायालय के लिए जो खुला है वह संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों, केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, से प्राप्त

सिद्धांतों को निर्धारित करना है।

1956 और एचजीएसटी अधिनियम और यह निर्धारित करने की दृष्टि से कुछ वस्तुओं या लेनदेन की जांच नहीं करना कि क्या उन वस्तुओं के संबंध में संपत्ति उप-खंड (ii) के अनुसार अनुबंधकर्ता को दी गई है और क्या कोई विशेष लेनदेन एक अंतर था - राज्य बिक्री. कार्य अनुबंध के निष्पादन के विभिन्न चरणों में शामिल वस्तुओं की विशाल विविधता के कारण ऐसा करना सरासर असंभव था। इसलिए, श्री सिब्लल ने आग्रह किया कि 1989 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10277 सहित रिट याचिकाओं के पहले सेट में यह निर्धारित करने के लिए अधिनियम के तहत कर अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या लेनदेन अंतर-राज्यीय बिक्री के बराबर है।

(14) विद्वान वकील की दलीलों की सराहना करने के लिए, संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों और संबंधित विभिन्न अधिनियमों का उल्लेख करना आवश्यक है।

(15) संसद ने 2 फरवरी, 1983 से संविधान (छियालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1982 पारित किया, सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने उक्त संशोधन अधिनियम के इतिहास का पता लगाने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसे लोकस क्लासिकस कहा जा सकता है। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मामला (सुप्रा)। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि संविधान के प्रारंभ से पहले, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 48 द्वारा प्रांतीय विधायिकाओं को बिक्री कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई थी। प्रांतीय विधायिकाओं ने क्षेत्रीय सांठगांठ के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए बिक्री-कर लगाने की शक्ति का प्रयोग किया, अर्थात्, उन्होंने बिक्री बनाने वाले एक या अधिक अवयवों को चुना और उन्हें बिक्री-कर लगाने का आधार बनाया। विधान। इससे विभिन्न प्रांतों द्वारा एक ही लेन-देन पर अनेक कराधान होने लगे। भारत के संविधान के तहत, अनुच्छेद 286 में बिक्री की स्थिति तय करने वाला एक स्पष्टीकरण शामिल था।

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद 121
वीह्रियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

स्पष्टीकरण निम्नलिखित शब्दों में था:

“उपखंड (ए) के प्रयोजनों के लिए, बिक्री या खरीद को उस राज्य में हुआ माना जाएगा जिसमें माल वास्तव में उस बिक्री या खरीद के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उस राज्य में उपभोग के उद्देश्य से वितरित किया गया है। बताएं, इस तथ्य के बावजूद कि - माल की बिक्री से संबंधित सामान्य कानून के तहत ऐसी बिक्री या खरीद के कारण माल की संपत्ति दूसरे राज्य में पारित हो गई है।”

स्पष्टीकरण की व्याख्या ने सर्वोच्च न्यायालय में ही मतभेद को जन्म दिया (देखें बॉम्बे राज्य बनाम यूनाइटेड मोटर्स (3), और बंगाल इम्युहिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य (4)। संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम द्वारा , 1956, अनुच्छेद 286 के खंड (1) में स्पष्टीकरण को हटा दिया गया था और उक्त अनुच्छेद के खंड (2) और (3) को नए खंडों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिससे संसद को माल की बिक्री या खरीद के निर्धारण के लिए सिद्धांत बनाने की शक्ति मिल गई। संविधान के अनुच्छेद 286 के खंड (1) में उल्लिखित किसी भी तरीके से होता है। सूची-1 में प्रविष्टि 92-ए भी शामिल की गई थी, जो संघ को माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने की शक्ति देती है, जहां ऐसी बिक्री या खरीद होती है। अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है। सूची-II की प्रविष्टि 54 के तहत बिक्री कर लगाने की राज्य की शक्ति को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि 92-ए के प्रावधानों के अधीन बनाया गया था। संविधान (छठे संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा संशोधित सूची-I की प्रविष्टि 92-ए और अनुच्छेद 286 के खंड (2) द्वारा दी गई शक्ति के अनुसरण में, संसद ने केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया। उक्त अधिनियम का लंबा शीर्षक, जहां तक वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, पढ़ता है: -

"यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार करने के लिए एक अधिनियम कि वाणिज्य के अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान या किसी राज्य के बाहर या भारत में आयात या निर्यात के दौरान माल की बिक्री या खरीद कब होती है।"

(16) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच इस बात को लेकर विवाद है कि क्या किसी भवन के निर्माण के दौरान भवन निर्माण ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए सामान की लागत को बिक्री कर के भुगतान के अधीन किया जा सकता है। उक्त संघर्ष को अंततः मद्रास राज्य बनाम मेसर्स गैनन बंकरले एंड कंपनी (मद्रास) लिमिटेड (5) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हल किया गया था। उसमें यह माना गया कि न तो निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को बेचने का कोई अनुबंध था और न ही उसमें चल संपत्ति के रूप में पारित संपत्ति थी। आगे यह माना गया कि एक भवन अनुबंध में, जो एक, संपूर्ण और अविभाज्य था, माल की कोई बिक्री नहीं होती थी और ऐसे अनुबंध में उपयोग की जाने वाली सामग्री बिक्री के समान मानते हुए बिक्री-कर के दायरे में नहीं आती थी। उपरोक्त निर्णय के आधार पर, भवन निर्माण ठेकेदार द्वारा कार्य अनुबंध के तहत प्राप्त राशि पर कोई बिक्री-कर नहीं लगाया जा सकता है, भले ही उसने माल की आपूर्ति की हो

(3) ए.1.आर 1953 एससी 252।

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद 123
वीह्रियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

(4) ए.ओय. 1955 एससी 661.

(5) ए.आईजेआर. 1958 एससी 560।

उड़डिंग्स के निर्माण के लिए. कुछ अन्य प्रकार के लेन-देन भी बिक्री की श्रेणी में नहीं आते थे, जिससे बिक्री-कर का भुगतान करना पड़ता था। कुछ अन्य मामलों में, शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कुछ अन्य लेनदेन बिक्री-कर लगाने के प्रयोजनों के लिए बिक्री की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये निर्णय बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मामले (सुप्रा) में नोट किए गए हैं। उन राज्य सरकारों की ओर से भी रिपोर्टें थीं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 269 के तहत बिक्री कर से राजस्व सौंपा गया था, ताकि माल की खेप के उपकरण के माध्यम से माल की अंतर-राज्य बिक्री पर लगाए जाने वाले केंद्रीय बिक्री कर से बड़े पैमाने पर बचा जा सके। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल और कार्य अनुबंध, किराया खरीद लेनदेन, फिल्मों के पट्टे आदि में स्थानीय बिक्री-कर का रिसाव। भारत के विधि आयोग ने अपनी 61वीं रिपोर्ट में संविधान में संशोधन का समर्थन किया। परिणामस्वरूप संविधान (छियालीसवाँ) संशोधन अधिनियम, 1982 पारित किया गया। बिक्री-कर लगाने के प्रयोजनों के लिए "माल की बिक्री या खरीद" अभिव्यक्ति की एक परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 866 में खंड (29-ए) द्वारा डाली गई थी। छियालीसवें संशोधन की मुख्य विशेषताएं, जो वर्तमान चर्चा के लिए प्रासंगिक हैं, इस प्रकार हैं:—i)

(i) अनुच्छेद 366 में एक नया खंड (29-ए) जोड़ा गया, जो इस प्रकार है:-

(29ए) "माल की बिक्री या खरीद पर कर" में शामिल हैं: -

- (a) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी सामान में संपत्ति के अनुबंध के अनुसरण के अलावा हस्तांतरण पर कर;
- (b) कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर;
- (c) किराया-खरीद या किशतों के भुगतान की किसी भी प्रणाली पर माल की डिलीवरी पर कर;

- (d) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए (किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए या नहीं) किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर कर;
- (e) किसी अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकद, विलंबित भुगतान या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की आपूर्ति पर कर
सोच-विचार;
- (f) किसी भी सेवा के माध्यम से या उसके हिस्से के रूप में या किसी भी अन्य तरीके से, भोजन या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या किसी पेय (चाहे या नशीला) की आपूर्ति पर कर, जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा, नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है, और किसी भी सामान के ऐसे हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति को हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा उन सामानों की बिक्री और उस व्यक्ति द्वारा उन सामानों की खरीद माना जाएगा। ऐसा स्थानांतरण, वितरण या आपूर्ति किसे की गई है;"
- (ii) अनुच्छेद 286 के खंड (3) को निम्नलिखित खंड के साथ प्रतिस्थापित किया गया था: -
- "(3) किसी राज्य का कोई भी कानून, जहां तक वह थोपता है, या थोपने को अधिकृत करता है, -
- (a) अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के लिए संसद द्वारा कानून द्वारा घोषित वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर; या
- (b) माल की बिक्री या खरीद पर कर, उप-खंड (बी), उप-खंड (सी) या उप-खंड ((डी) (सीक्लॉज ((29-ए)) में निर्दिष्ट प्रकृति का कर है। (अनुच्छेद 366 में, कर लगाने की प्रणाली और कर की अन्य घटनाओं के संबंध में ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन होंगे जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।)

(17) संविधान की 46 संशोधन के बाद, H GST अधिनियम को हरियाणा सामान्य बिक्री-कर (संशोधन और मान्यकरण) अधिनियम, 1984 (हरियाणा अधिनियम संख्या 11, 1984) द्वारा संशोधित किया गया था, जो 18 अप्रैल के हरियाणा गैसेट (अतिरिक्त) में प्रकाशित हुआ था। 1984. संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) में "माल की बिक्री या

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद 125
वीहरियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

'खरीद' अभिव्यक्ति की संशोधित परिभाषा को दो भागों में विभाजित किया गया था, अर्थात्, 'खरीद' और 'बिक्री'। 'खरीद' शब्द को खंड (जे) में परिभाषित किया गया था और 'बिक्री' शब्द को एचजीएसटी अधिनियम की धारा 2 के खंड (1) में परिभाषित किया गया था। प्रासंगिक उप-खंडों को अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के प्रावधानों से हटा दिया गया था और एचजीएसटी अधिनियम में निगमित किया गया था। आगे यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि खंड (जे) और (1) में क्रमशः 'खरीद' और 'बिक्री' की दोनों परिभाषाओं में प्रयुक्त भाषा यथोचित परिवर्तनों के साथ समान है। इसलिए, आगे होने वाली चर्चा में, हरियाणा अधिनियम के खंड (1) में परिभाषित बिक्री के संदर्भ में खंड (जे) में परिभाषित खरीद का संदर्भ शामिल होगा।

W.s.jst इंडिया कॉटन मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद f^j
वीहरियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

जे 18

(1[^]) डब्ल्यूएम आर[^]वैप्ट संशोधन अधिनियम * हेटी6<ए सामान्य बिक्री-
कर (संशोधन) अधिनियम, 1987 (हरियाणा एट: संख्या; #1987) है, जो 2 अप्रैल के
हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। 1987. इंटर फिल्म,
निम्नलिखित; नोट नं.-S w[^]Wwied खंड (1) में: -

^qte/?—उपखंड (ii) और spb-cl[^]qse, (jv> >so>£ar क्योंकि यह 'goqds
से संबंधित है, स्वाभाविक रूप से, .[^](इसमें प्रयुक्त-
.बीपीवाईडीजेपी[^] तंबू, आइसोलेट्स की संरचना: इहलविदरी, क्रॉकरी,
बर्तन, फर्नीचर, और एमएल अन्य सामान टेंट डीलर के साथ-साथ
अन्य सहयोगी डीलरों द्वारा प्रकाश प्रयोजनों, बिजली मीटर और
क्यूडीईरेशन के लिए निपटाए जाते हैं। जल मीटर 1 अप्रैल 1987 से
लागू होंगे।"

इसके बाद हरियाणा जनरल सेल्स (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का
हरियाणा अधिनियम संख्या 1) मार्च में हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित हुआ।
17, 1989. iReferenoe केवल उन संशोधनों पर लागू होता है जो IWT उद्देश्यों
के लिए प्रासंगिक हैं।

डियो को

(i) नए जोड़े गए dause(ba) में 'ठेकेदार' शब्द को इस प्रकार परिभाषित
किया गया है: noaat ".di (n)

<ली. ,हाथो

"ठेकेदार" का अर्थ कोई भी व्यक्ति है जो स्वयं या अपने उप-ठेकेदार
के माध्यम से काम करता है? अनुबंध।"

'ddB'jVOHf

(ii) शब्द "ठेकेदार" को b[^] qjajise (bb) के रूप में परिभाषित किया गया
था; ;उफ़ीदेरी»qw »
एनएफसी

(([^]जूस:आईओ जेएलडब्ल्यू)

"ठेकेदार" का अर्थ है कोई भी प्रति[^] (या)r)yh[^]

किसी कार्य को अनुबंध के रूप में फिट करना, है

?[^]u|[^]).IfnGjh(.q -dl bna

.(£)88£ बीआरटी (ई)88एस

W.s.j^st इंडिया कॉटन मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फ़रीदाबाद f^j
वीहरियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

१.(iii) मोटे के बाद-?, खंड (जे) में \$snly^^^fICWJWf निम्नलिखित
परंतुक जोड़ा गया:—Msrforoq

बशर्ते कि एक मृतक, जिसने "i"iarg"hto<^J बनाया (हम/ओटी उसके
पंजीकरण का प्राधिकारी बोसेबटि फिकैस^tt! इसके तहत, 'एम"; केंद्रीय
बिक्री-कर ^tt^d 'अप्रैल के 18वें दिन से अवधि को ध्यान में रखते हुए,
एम8आईबीएमडब्ल्यूएल^आरएफ^आर्क, 1987 .. फिर वह कर का भुगतान
करने के लिए उत्तरदायी है।^ के बारे में

उनकी

पंजीकरण प्रमाणपत्र ^ffl^P^eWiiB® कार्यो का; अनुबंध,
ga^ripaK ^i^ofert^15 उद्देश्य के रूप में

उप-खंड (ii) और उप-खंड (iv) 18 अप्रैल, 1984 से लागू माने जाएंगे।

(iv) निम्नलिखित नोट 3 भी जोड़ा गया:

"नोट 3. उप-खंड (ii) के अंतर्गत आने वाली खरीद को राज्य के भीतर हुई माना जाएगा यदि कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल सामान निष्पादन में उनके उपयोग के समय राज्य के भीतर हैं कार्य अनुबंध।"

(v) अभिव्यक्ति "कार्य अनुबंध" को खंड (पीए) में इन शब्दों में परिभाषित किया गया था: -

"कार्य अनुबंध" का अर्थ नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के निष्पादन के लिए कोई समझौता है-

- (i) किसी भवन, सड़क, दीवार, पुल, तटबंध, बांध या अन्य अचल संपत्ति का निर्माण, फिटिंग, सुधार या मरम्मत; या
 - (ii) किसी भी चल संपत्ति का संयोजन, निर्माण, स्थापना, मरम्मत, फिटिंग, परिवर्तन, अलंकरण, सन्मिश्रण, परिष्करण, सुधार, प्रसंस्करण, उपचार या अनुकूलन, चाहे वह किसी अचल संपत्ति से जुड़ा हो या नहीं;
- और प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्य, बिजली मीटर और पानी के मीटर ऐसे काम का हिस्सा हैं।

(19) संविधान और अनुच्छेद 269(3) और 286(2) यानी केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 के अनुसरण में बनाए गए संसदीय कानून के अनुसार, राज्य विधानमंडल निम्नलिखित बिक्री पर कर लगाने के लिए सक्षम नहीं है या खरीदारी :—i()

- (i) जहां अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री या खरीद होती है, ऐसी बिक्री बिक्री-कर अनुच्छेद 269(3) लगाने के प्रयोजनों के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे है।
- (ऐसा इसलिए है क्योंकि सूची-II की प्रविष्टि 54 स्वयं सूची-I की प्रविष्टि 92-ए के अधीन है। सूची-I की प्रविष्टि 92-ए संसद को अंतर के दौरान होने वाली बिक्री पर कर लगाने की विशेष शक्ति देती है। -राज्य व्यापार या वाणिज्य)।

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद 125
वीहरियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

(ii) जहां बिक्री राज्य के बाहर होती है,—(संविधान का व्यापक अनुच्छेद 286(1)(ए))।

(iii) जहां बिक्री देश में आयात और निर्यात के दौरान होती है, - (अनुच्छेद 286(1)(बी) के तहत)।

(iv) ऐसी अन्य सीमाएँ, यदि कोई हों, जो संसद इनके संबंध में लगा सकती है:

(a) अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के लिए संसद द्वारा कानून द्वारा घोषित वस्तुओं की बिक्री; और

(b) सिस्टम के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के उप-खंड (बी), उप-खंड (डी) या उप-खंड (डी) में निर्दिष्ट प्रकृति में कर के रूप में वस्तुओं की बिक्री या खरीद लेवी, दरें या अन्य घटनाएं जो संसद द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। (अनुच्छेद 286(3) देखें)।

(20) केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 4(2), (एक राज्य के अंदर बिक्री या खरीद होने पर एक प्रावधान बनाती है। यह इस प्रकार है: -

"(2) माल की बिक्री या खरीद को राज्य के अंदर माना जाएगा यदि माल राज्य के भीतर है-

(a) विशिष्ट या सुनिश्चित माल के मामले में, बिक्री का अनुबंध किए जाने के समय; और

(b) अज्ञात या भविष्य के सामान के मामले में, उस समय; विक्रेता या खरीदार द्वारा बिक्री के अनुबंध के लिए उनके विनियोग की, चाहे दूसरे पक्ष की सहमति ऐसे विनियोग से पहले या बाद में हो।

जब बिक्री किसी राज्य के अंदर होती है, तो इसे अन्य सभी राज्यों के बाहर

हुआ माना जाएगा (धारा 4(1)) उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा परिभाषित अंतरराज्यीय बिक्री इस प्रकार है: -

“3. अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री या खरीद कब होने के लिए कहा जाता है: माल की बिक्री या खरीद को माना जाएगा

अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान यदि बिक्री या खरीद-

एफए) एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही का अवसर; या

(बी) एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन के दौरान माल के स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होता है।

स्पष्टीकरण1. xxxxxx

स्पष्टीकरण2. xxxx xx

केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 4 को स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 3 के अधीन बनाया गया है।

एफ21) केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 और 15, किसी राज्य के भीतर घोषित माल की बिक्री या खरीद पर कर के संबंध में, जहां तक बिक्री-कर कानून की बात है, उसमें निर्दिष्ट प्रतिबंध और शर्तें शामिल हैं। राज्य चिंतित है।

(22) पुनरावृत्ति के जोखिम पर भी, जो प्रस्ताव सामने आते हैं उन्हें इस प्रकार कहा जा सकता है।

सबियानी 6b£C^ie>&tatte2«^8i@bJr64iS(no<Hft)#iff^bW: यदि नमक पर कर लगाया जाता है--

iobn;j ss absoi ii

एस3Blq wteWU^WicU ^W^^

—oisiS Orii nijiii w p'tK aboog Orii !i oipiB g ओबियानी (बी) राज्य के

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद 127
वीह्रियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

बाहर बिक्री हो रही है।

ओर्नी ओरी जेबी .aboog. बोनिब्राँक्सर- "ओ ऑयलीउका ट ओएसो ऑन)
एनआर (एस) (सी) एल्स इन टीएफसीओ^ओ डब्ल्यू^{से}
देश।

एमिट ओरी है, अबूग ओइउइउल आईओ बानीBhsDaBnu लो ओसो ओरी नी
(डी)

aril yJ^Itb ^{^(MlftW ^h^^j^Jouestrictions and jsriio orii W^jteniHS^}
a^{cP^a^ufe WJb^y} कानून लागू ".noiiBiid&iW5^^ ffter^pMB^ fsllipgitWi
उप-खंड (बी)).

सिल्ली (iii) The Parliament has the exclusive power to formulate
मोर्न (iii) The Parliament has the exclusive power to formulate
principles for determining when a sale or purchase takes
place—

GIAS PQODfiliW^{&felSISift} से SJ.VA Pf WJHW .8" -H3TMI

TOI S2RITO3 3HT W HDAH SWAT ., ■iki io @nA

HWiffW'WM'iff lhe Orfi ni sfi[^] inIdii©ic4jerHBo(bf

संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) का (सी) या (डी)।

(23) एचजीएसटी अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (1) के तहत
संवैधानिक वैधता या नोट -3 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इसमें
इस्तेमाल किए गए शब्द "बिक्री" के दायरे को अंतर-राज्य तक सीमित करने
वाले किसी भी शब्द के अभाव में बिक्री, नोट का यह अर्थ लगाना संभव था
कि "बिक्री" शब्द में अंतर-राज्यीय बिक्री भी शामिल है। यदि ऐसा किया गया,
तो अंतर-राज्यीय बिक्री को भी एचजीएसटी अधिनियम, 1973 के दायरे में लाया
जाएगा। जो राज्य विधानमंडल की शक्तियों से परे है। यह ■ ऊपर पैराग्राफ
22 में तैयार किए गए प्रस्तावों का उल्लंघन होगा। श्री एस चड्ढा, श्री राजे
राम अग्रवाल और श्री आरसी डोगरा, रिट याचिकाओं के विभिन्न सेटों में
याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित हुए विद्वान वकील ने कहा कि वे होंगे।
संतुष्ट हो तो. नोट-3 का तात्पर्य यह है कि यह यहीं तक सीमित था। केवल
अंतर-राज्यीय बिक्री और इसके दायरे में अंतर-राज्यीय बिक्री शामिल नहीं है।
यदि इस प्रकार है कि नोट 3 की संवैधानिक वैधता को याचिकाकर्ताओं के
विद्वान वकील द्वारा किसी अन्य आधार पर चुनौती नहीं दी गई है।

(24) हमारा मानना है कि नोट 3 राज्य विधानमंडल की शक्तियों का अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। इस निष्कर्ष के समर्थन में हमारे कारण अनुसरण करते हैं।

(25) अनुच्छेद 269(3) और 286(2) के तहत संसद को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, संसद ने केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया है। उक्त अधिनियम (i) राज्य के बाहर होने वाली बिक्री या खरीद से संबंधित है। : (ii) भारत के क्षेत्र से बाहर माल के आयात या निर्यात के दौरान होने वाली बिक्री या खरीद; और (iii) अंतरव्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली बिक्री या खरीद। एचजीएसटी अधिनियम, 1973 की धारा 12 द्वारा इन सभी तीन प्रकार की बिक्री को स्पष्ट रूप से एचजीएसटी अधिनियम, 1973 के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, धारा 12 में एक गैर-अस्थिर खंड को शामिल करके एक अधिभावी प्रभाव दिया गया है। धारा 27 धारा 12 के अंतर्गत आने वाले माल को कर योग्य टर्नओवर से बाहर करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान करती है। जैसा कि असेसिंग अथॉरिटी बनाम मेसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मिग में निर्धारित किया गया है। कंपनी लिमिटेड (6) यह व्याख्या का एक सुस्थापित नियम है कि किसी एक खंड को अलग करके नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए; प्रत्येक भाग दूसरे के अर्थ पर प्रकाश डालता है, - (पृष्ठ 1613 पर अनुच्छेद 5 देखें) इस स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि शब्द बिक्री* एम नोट 3 केवल अंतर-राज्य बिक्री तक ही सीमित है, नोट 3 को नीचे पढ़ेंगे केवल अंतर-राज्य बिक्री तक ही सीमित रहें।

(6) एआईआर 1981 एससी 1610।

(26) दूसरे तर्क पर आते हुए, हमारे विचार में, श्री सिब्लल यह इंगित करने में स्पष्ट रूप से सही हैं कि यह अभिव्यक्ति "कार्य अनुबंध" की व्यापक परिभाषा नहीं है, जिसका वर्तमान उद्देश्यों के लिए कोई महत्व है, बल्कि यह कर योग्य घटना है। करयोग्य घटना के निर्धारण के लिए मुख्य परीक्षण यह

है कि किस घटना के घटित होने पर कर दायित्व आकर्षित होता है (देखें मेसर्स गुडइयर इंडिया लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (7)। यह विवादित नहीं है कि वर्तमान मामले में, करयोग्य घटना एचजीएसटी अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (1) के प्रासंगिक उप-खंड के अर्थ के भीतर माल का स्थानांतरण, वितरण या आपूर्ति है। दूसरे शब्दों में, कर योग्य घटना माल में संपत्ति का हस्तांतरण है (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल है। "कार्य अनुबंध" की परिभाषा राज्य विधानमंडल के संविधान या शक्तियों के दायरे से बाहर नहीं है क्योंकि यह व्यापक शर्तों में है। इसलिए, हमारे पास है, इस तर्क को अस्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है।

(27) यह हमें तीसरे विवाद पर लाता है। एचजीएसटी अधिनियम की अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि 14 में "रेयान, कृत्रिम रेशम या नायलॉन सहित सूती, ऊनी या रेशमी वस्त्रों की सभी किस्मों को संदर्भित किया गया है, लेकिन इसमें कालीन, ड्रगगेट्स, ऊनी ड्यूरी, सूती फर्श ड्यूरी, कंबल, गलीचे और सभी शामिल नहीं हैं। ड्रायर फेल्ट की वे किस्में जिन पर बिक्री-कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है। प्रविष्टि 32 लॉटरी टिकटों को संदर्भित करती है। "शर्तें और अपवाद" के लिए बने तीसरे कॉलम में उक्त दोनों प्रविष्टियों के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया है। एचजीएसटी अधिनियम, 1973 की धारा 6 में कराधान की घटनाओं को निर्धारित करते समय एक प्रावधान शामिल है कि उक्त धारा में शामिल कुछ भी उस डीलर पर लागू नहीं होगा जो विशेष रूप से अनुसूची 'बी' में निर्दिष्ट वस्तुओं का कारोबार करता है। ये प्रावधान धारा 8(2ए) के आधार पर केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 के तहत बिक्री-कर के मूल्यांकन के लिए लागू होते हैं। यह दिखाने के लिए किसी बड़े तर्क की आवश्यकता नहीं है कि अनुसूची 'बी' में उल्लिखित विभिन्न सामान ऐसे सामान की बिक्री या खरीद के संदर्भ में हैं। दूसरे शब्दों में, यदि लॉटरी टिकटों को लॉटरी टिकटों के रूप में बेचा जाना है, तो जब तक वर्तमान प्रावधान जारी रहेंगे तब तक बिक्री कर लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। वस्त्रों के मामले में भी यही सच है। सवाल उठता है कि क्या जिस चीज पर कर लगाने की मांग की गई है वह लॉटरी टिकट के रूप में लॉटरी

टिकट है या कपड़ा के रूप में कपड़ा। हमारी नजर में ऐसा नहीं है. धारा 2 के खंड (ii), खंड (1) के संदर्भ में कार्य अनुबंध के निष्पादन में माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर लगाने की मांग की गई है। इसमें कागज आदि शामिल होंगे जिनका उपयोग लॉटरी टिकट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। . इसी प्रकार,

(7) एआईआर 1990 एससी 781।

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फ़रीदाबाद 131
वीहरियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

वस्त्रों के मामले में, जिस पर कर लगाने की मांग की गई है वह वह सामान है जो धारा 2 के खंड (1) के उक्त उप-खंड (ii) के दायरे में आएगा और कुछ नहीं। हमें सलाह दी जाती है कि हम इस प्रश्न की जांच करें कि कौन सा सामान उप-खंड (ii) के दायरे में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जब भी प्रश्न उठाया जाए तो निर्णय लेने का अधिकार कर निर्धारण प्राधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इन कारणों से, हमें इस विवाद में कोई सार नहीं दिखता।

(28) अगले तर्क के साथ, यह कहा जा सकता है कि एचजीएसटी अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (जे) और (1) के उप-खंड (ii) और (iv) को पहली बार 1984 के हरियाणा अधिनियम संख्या 11 द्वारा डाला गया था। 1987 के हरियाणा अधिनियम संख्या 11 के अनुसार, उप-खंड (ii) और उप-खंड (iv) से संबंधित कुछ निर्दिष्ट वस्तुएं बाद की तारीख से प्रभावी होनी थीं, अर्थात्, अप्रैल 1987 का पहला दिन यानी ठीक पहले की तारीख। राज्य राजपत्र में संशोधन अधिनियम का प्रकाशन। हालाँकि, बाद में, यह सरकार के ध्यान में आया कि कुछ डीलरों ने, वास्तव में, उप-खंड (ii) के अंतर्गत आने वाले लेनदेन पर और जहाँ तक खंड (iv) में उल्लिखित वस्तुओं पर बिक्री कर लगाया था। 1989 के हरियाणा अधिनियम संख्या 1 द्वारा, इसलिए, उप-खंड (ii) और नोट 2 में निर्दिष्ट उप-खंड (iv) में निर्दिष्ट वस्तुओं को 18 अप्रैल, 1984 से प्रभावी किया गया था, वह तारीख जब छियालीसवें संशोधन का पालन किया गया था हरियाणा सामान्य बिक्री-कर अधिनियम, 1973 को 1 अप्रैल, 1987 के बजाय नोट 2 के खंड (जे) और (1) में एक परंतुक जोड़कर संशोधित किया गया था। आक्षेपित संशोधन का प्रभाव ऐसा है मानो पिछले अधिनियम द्वारा निर्धारित तिथि, अर्थात् 1 अप्रैल, 1987 को मिटा दिया गया हो और 18 अप्रैल, 1984 लिखा गया हो। शीर्ष न्यायालय ने शॉनराव बनाम डीएम थाना (8) में सिद्धांत को इन शब्दों में समझाया: -

"नियम यह है कि जब कोई अगला अधिनियम पहले वाले अधिनियम में इस तरह से संशोधन करता है कि वह खुद को, या खुद के एक हिस्से को पहले वाले में शामिल कर सके, तो उसके बाद पहले वाले अधिनियम को पढ़ा और समझा जाना चाहिए (सिवाय इसके कि इससे कोई समस्या उत्पन्न होगी) प्रतिकूलता, असंगतता या बेतुकापन (बदले हुए शब्दों के रूप में) को पहले के अधिनियम में कलम और स्याही से लिखा गया था और पुराने शब्दों को हटा दिया गया था ताकि उसके बाद संशोधित अधिनियम को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता न हो। इंग्लैंड में यह नियम है: वैधानिक निर्माण पर क्रॉफर्ड

(8) एआईआर 1952 एससी 3241

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फ़रीदाबाद 132
वीह्रियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

देखें, पृष्ठ 110; और यह वह कानून है जो प्रिवी:

परिषद ने केशोराम पोद्दार बनाम नंदलाल मल्लिक, (एआईआर 1927 पीसी 97) मामले में भारत में आवेदन किया।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि विधानमंडल के पास किसी कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की पर्याप्त शक्तियां हैं।

(29) तर्क का जोर यह है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य में उन्नत तकनीक, विशेषज्ञता शामिल है और मुद्रण के मामले में, विशेष रूप से लॉटरी टिकटों में याचिकाकर्ता प्रिंटिंग प्रेस में अनुबंधकर्ता द्वारा उच्च स्तर का विश्वास जताया गया है। छपाई के मामले में कागज की आपूर्ति और वर्कों की रंगाई और छपाई के मामले में रंगों और रंगों का उपयोग, केवल संयोगवश अनुबंधकर्ता के पास जाता है और इसलिए, वे बिक्री-कर के दायरे में नहीं आते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा तमिलनाडु राज्य बनाम आनंदम विश्वनाथम (9) पर भरोसा रखा गया है। उस मामले में सवाल यह था कि क्या कर योग्य टर्नओवर में प्रिंटिंग और ब्लॉक बनाने का शुल्क शामिल होगा या नहीं। आंध्र प्रदेश सरकार बनाम गुंटूर टोबैको लिमिटेड (10) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि अनुबंध में अलग से दिखाए गए कागज की लागत कर के लिए उत्तरदायी होगी और उस लागत को छोड़कर कागज और अन्य संबंध में आपूर्ति की गई सामग्री, अनुबंध कार्य और श्रम के लिए एक अनुबंध था और बिक्री-कर के लिए कोई दायित्व नहीं हो सकता था। हाई कोर्ट के मुताबिक इसमें प्रिंटिंग चार्ज शामिल होगा. ऐसा पाया गया कि प्रश्नपत्र छपने के बाद ब्लॉक नष्ट कर दिये गये थे। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि ब्लॉकों की बिक्री या उनमें संपत्ति के हस्तांतरण का कोई सवाल ही नहीं था। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपीलें उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गईं। उपरोक्त मामले में इस प्रकार कागज की लागत को बिक्री-कर के दायरे में रखा गया था। उनके आधिपत्य ने आनंदम विश्वनाथन के मामले (सुप्रा) में गुंटूर टोबैको लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में पहले निर्धारित परीक्षणों को मंजूरी दे दी, गुंटूर टोबैको लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में यह निर्धारित किया गया था कि काम के लिए अनुबंध तीन रूपों में से कोई भी ले सकता है: -

- (1) पारिश्रमिक और मूल्य पर कार्यो के निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री की आपूर्ति के लिए किए गए कार्य के लिए। इसे काम और माल की बिक्री के लिए एक समग्र अनुबंध माना गया था,

(9) एआईआर 1989 एससी 962।

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद 134
वीह्रियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

(10) एआईआर 1965 एससी 1396।

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद 135
वीह्रियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

(11) ऐसे कार्य के लिए जिसमें इसे कार्य के निष्पादन के लिए एक सामग्री का उपयोग सहायक या अनुबंध माना गया जिसमें माल की बिक्री आकस्मिक हो।

(111) काम और सामग्री के कोई बिक्री नहीं हुई क्योंकि हालांकि माल उपयोग या आपूर्ति के लिए जो में संपत्ति पारित हो गई, लेकिन यह अनुबंध के निष्पादन में सहायक नहीं है बल्कि स्वैच्छिक या निःशुल्क है।

आनंदम विश्वनाथन का मामला(सुप्रा) को उपरोक्त श्रेणी (ii) में माना गया था। श्री आरसी डोगरा और श्री रणधीर-चावला जिन अन्य अधिकारियों पर भरोसा करते हैं वे हैं:

- (1) *सहायक. बिक्री-कर अधिकारी और अन्य*वी. बीसी केम, (177) 39 एसटीसी 237;
- (2) *हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड*बनाम उड़ीसा राज्य, (1984) 55 एसटीसी 327;
- (3) *विक्रय-कर आयोग, म.प्र*वी. रत्ना फाइन आर्ट्स प्रिंटिंग प्रेस, (1984) 56 एसटीसी 77; और
- (4) *आगरा यूनिवर्सिटी प्रेस पालीवाल पार्क*वी. बिक्री कर आयुक्त, (1984) 56 एसटीसी 317।

ये प्राधिकरण संविधान के छियालीसवें संशोधन और बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं के मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं, जिसमें इसे पृष्ठ 1390 पर पैरा 36 में निर्धारित किया गया था। निम्नलिखित नुसार :-

“46वें संशोधन के बाद कार्य अनुबंध जो अविभाज्य था, कानूनी कल्पना द्वारा एक अनुबंध में बदल दिया गया है जो एक माल की बिक्री के लिए और दूसरा श्रम और सेवाओं की आपूर्ति के लिए विभाजित है। 46वें संशोधन के बाद राज्यों के लिए कार्य अनुबंध में शामिल वस्तुओं के मूल्य पर उसी तरह बिक्री कर लगाना संभव हो गया है, जिस तरह भवन निर्माण अनुबंध में आपूर्ति की गई वस्तुओं और सामग्रियों की कीमत पर बिक्री कर लगाया जाता था। दो अलग-अलग और में दर्ज किया गया था जैसा कि ऊपर बताया गया है, अलग-अलग हिस्से।

इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि कागज आदि में संपत्ति का हस्तांतरण केवल आकस्मिक था और पॉन्ट्रेक्ट एक सीपीएमपोजिट था। हम सलाहपूर्वक इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं कि खंड (ii) के अनुसार किस सामान के संबंध में अनुबंधकर्ता के पक्ष में उचित रूप से पारित होता है और किसमें नहीं। चीजों की प्रकृति में, यह निर्धारित करने के लिए कर अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या विचाराधीन सामान बिक्री कर लगाने के प्रयोजनों के लिए खंड (ii) के तहत कवर किया गया है या नहीं।

(30) अपने तर्कों के समर्थन में, श्री सिब्लल ने पद्मैया वाणिज्यिक निगम बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (11), रंजीत कुमार बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, नायडूपेटा और अन्य (12), 20वीं सेंचुरी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य वाई पर भरोसा जताया। महाराष्ट्र राज्य (13), बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (14), साथ ही 11 फरवरी, 1992 को 1989 के सीडब्ल्यूपी संख्या 15583 में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच का निर्णय, जिसमें संवैधानिक संबंधित राज्य अधिनियमों में किए गए समान प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा गया था - श्री सिब्लल ने पेस्ट कंट्रोल इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (15) के बीच अंतर करने के लिए लड़ाई लड़ी, जिसे याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस आधार पर उद्धृत किया कि मामला संबंधित है सेवा अनुबंध को कार्य अनुबंध या बिक्री अनुबंध से अलग करना। जिन अधिकारियों पर श्री सिब्लल ने भरोसा किया, वे निस्संदेह उनके द्वारा उठाए गए रुख का समर्थन करते हैं। इसलिए, हमारे विचार में, 1989 के हरियाणा संशोधन अधिनियम संख्या 1 द्वारा संशोधित धारा 2 के प्रावधानों को संवैधानिक रूप से वैध माना जाना चाहिए।

(31) विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या मेसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, 1989 के सीपी नंबर 10227 में याचिकाकर्ता और कुछ अन्य संबंधित याचिकाओं द्वारा ग्रे कपड़े की फिनिशिंग और आकार आदि की विशेष प्रक्रिया एक है? अंतरराज्यीय बिक्री.

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फ़रीदाबाद 137
बनाम हत्याना राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)
उक्त गतिविधि का वर्णन याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका संख्या
10227/1989 के पैराग्राफ 6 में इन शब्दों में किया गया है: -

(32) याचिकाकर्ता ग्रे कपड़े का उपयोग करके वस्त्रों का निर्माण और
प्रसंस्करण करता है। उसके लिए याचिकाकर्ता

- (11) (1987)66एस.टीसी26।
- (12) (1988)71एस.टीसी502-
- (13) (198.9)75एस.टीसी217.
- (14) (1990)79एस.टीसी442।
- (15) (1989)75एस.टीसी188 (पटना)।

ग्रे कपड़े को कपड़े में संसाधित करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता के कारखाने में हरियाणा राज्य के बाहर से उनकी पार्टियों का ग्रे कपड़ा लाया जाता है। माल में संपत्ति का स्वामित्व, चाहे वह ग्रे कपड़ा हो या पोसीस्ड कपड़ा, उसके मूल मालिक के पास निहित है, न कि याचिकाकर्ता के पास। याचिकाकर्ता केवल रंग और रसायनों का उपयोग करके भूरे कपड़े को संसाधित करता है और कपड़े के मालिक से श्रम शुल्क प्राप्त करता है और कपड़े को हरियाणा राज्य के बाहर फिर से निर्यात करता है। संक्षेप में, यह एक शुद्ध अंतर-राज्य लेनदेन है।"

Theft ii' लिखित बयान के संबंधित पैराग्राफ में बताए गए तथ्यों का खंडन व्यक्त करता है। इसके बजाय इसमें कहा गया है कि पैराग्राफ 6 की सामग्री को केवल उस सीमा तक ही स्वीकार किया जाता है, जहां तक याचिकाकर्ता कपड़े के प्रसंस्करण के व्यवसाय में लगा हुआ है। रिट याचिका के पैराग्राफ 6 में बताए गए भौतिक तथ्यों को लिखित बयान में कहीं और भी विवादित किया गया है। विशिष्ट खंडन के अभाव में, हम अनुच्छेद 6 में दिए गए तथ्य के कथनों को निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं और यह जांचने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या गतिविधि अंतर-राज्यीय बिक्री के बराबर है।

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फ़रीदाबाद 138

बनाम हत्याना राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

(32) केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 में कहा गया है कि माल की बिक्री या खरीद को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माना जाएगा यदि बिक्री या खरीद के कारण आवाजाही होती है। एक राज्य से दूसरे राज्य तक माल. हमें उस अनुभाग के शेष भाग का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है। दूसरे शब्दों में, किसी बिक्री को अंतर-राज्यीय बिक्री मानने के लिए धारा 3 में निर्धारित परीक्षण यह है कि क्या यह एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही का अवसर देता है। इस धारा की व्याख्या शीर्ष न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में की गई थी और यह माना गया था कि यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में जीडीबीडीएस की आवाजाही एक अनुबंध या बिक्री के अनुबंध की घटना का परिणाम है, तो बिक्री एक अंतर-राज्य बिक्री है। यदि बिक्री के अनुबंध में स्वयं एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के लिए एक शर्त शामिल है, तो यह निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई नहीं होती है कि बिक्री एक अंतर-राज्य बिक्री है। भले ही यह अनुबंध द्वारा प्रदान नहीं किया गया हो, लेकिन ऐसा आंदोलन एक अनुबंध का परिणाम है या अनुबंध की एक घटना है, यह एक अंतर-राज्यीय बिक्री होगी। यह देखना प्रासंगिक नहीं है कि माल में संपत्ति किस राज्य में गुजरती है यह निर्धारित करने के लिए कि बिक्री एक अंतर-राज्यीय बिक्री है या नहीं। यह भी जरूरी नहीं कि बिक्री हो ही

ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस तरह के आंदोलन का आह्वान किया है। (देखें यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केजी खोसला एंड कंपनी (16), ऑयल इंडिया लिमिटेड बनाम, कर अधीक्षक और अन्य (17), मेसर्स साहनी स्टील एंड प्रेस वर्क्स लिमिटेड और अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य (18), और परियोजनाएं और सेवा केंद्र और अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य और अन्य (19)। पहले से वर्णित तरीके से कपड़े का प्रसंस्करण धारा 2 के खंड (1) के उप-खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए बिक्री माना जाता है। एचजीएसटी अधिनियम, 1973 के। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मामले (सुप्रा) में यह निर्धारित किया गया है कि जब कानून कोई कानूनी कल्पना करता है, तो ऐसी कल्पना को उसके तार्किक अंत तक ले जाया जाना चाहिए। पूर्ण प्रभाव देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए इसके लिए। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, इसलिए, मानी गई बिक्री को उचित रूप से तथाकथित बिक्री माना जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यह वह बिक्री है जो उस भूरे कपड़े में माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने का अवसर देती है। हरियाणा राज्य के बाहर से अनुबंधकर्ताओं द्वारा भेजा जाता है; इसे हरियाणा राज्य के फ़रीदाबाद में संसाधित किया जाता है और उसके बाद इसे अनुबंधकर्ताओं को वापस भेज दिया जाता है। इसलिए, कपड़े की आवाजाही एचजीएसटी अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (1) के उप-खंड (ii) के अर्थ के भीतर बिक्री के अनुबंध द्वारा होती है। इसलिए, हमारा विचार है कि कहा गया है केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अर्थ के अंतर्गत लेनदेन अंतर-राज्यीय बिक्री के बराबर है।

(33) श्रीमान आईसी रणधीरी चावला, एम/एस3 थॉम्पसन! एसपी (इंडिया) प्रा. लिमिटेड ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का मूल्यांकन एचजीएसटी अधिनियम के साथ-साथ केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम दोनों के तहत किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान के छियालीसवें संशोधन के बाद, केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम के तहत, याचिकाकर्ता पर केवल इस आधार पर कोई बिक्री-कर नहीं लगाया जा सकता है कि छियालीसवें संशोधन के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 366 में खंड (29-ए) जोड़ा गया था। हम इसमें कोई संदेह नहीं मानते हैं यदि कर केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम के तहत लगाया जाना है, तो कर अधिकारी केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों से आगे नहीं बढ़ सकते। अनुच्छेद 366 में खंड (29-ए) के सम्मिलन में केवल व्यय की परिभाषा शामिल है इजहार

- (16) (1979)43एस.टीसी457।
- (17) (1975)35sS.TC445।
- (18) एआईआर11985 एससी1754।
- (19) (1991)82एस;.टीसी89।

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद 141
वीहरियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

संविधान के विभिन्न प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए "बिक्री और खरीद पर कर"। यह संसद को "बिक्री" शब्द सहित केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम में प्रयुक्त प्रासंगिक अभिव्यक्तियों की परिभाषा को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के लिए एक सक्षम प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है यदि इसका उद्देश्य खंडों में विभिन्न लेनदेन के संबंध में बिक्री-कर लगाना है (ए)) अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के (जे) तक, मोटे तौर पर उन तर्ज पर जिन पर विभिन्न राज्यों ने स्थानीय सामान्य बिक्री-कर अधिनियमों में संशोधन किया है। चूंकि ऐसा नहीं किया गया है, यह कर अधिकारियों के लिए खुला नहीं है केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 के तहत उन लेनदेन पर बिक्री-कर लगाने के लिए आगे बढ़ना, जो केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 2(जी) में परिभाषित बिक्री के बराबर नहीं हैं।

(34) कृषि आयकर और बिक्री कर (कानून) के उपायुक्त - एर्नाकुलम बनाम पीके बिरुम्मा (20) में, निर्धारित टायरों की रीट्रेडिंग के व्यवसाय में लगा हुआ था। वह केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत डीलर थे। संविधान के छियालीसवें संशोधन के बाद, टायर रीट्रेडिंग व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की कुछ वस्तुओं को शामिल करने के लिए उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन किया गया था। इसके बाद, इसमें शामिल समय को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 2 (जी) में परिभाषित अनुसार रीट्रेडिंग बिक्री की राशि नहीं है, बल्कि यह केवल एक कार्य अनुबंध था। ट्रिब्यूनल ने माना कि संविधान के छियालीसवें संशोधन के आधार पर बिक्री में कार्य अनुबंध भी शामिल है। एक पुनरीक्षण याचिका पर, यह उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। केरल ने कहा कि यद्यपि संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा अनुच्छेद 366 में खंड (29-ए) शामिल किया गया था, इसने विधानमंडल को निष्पादन में शामिल वस्तुओं पर संपत्ति के कराधान के लिए प्रावधान करने का उचित अधिकार दिया। कार्य अनुबंध का केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 में किए गए संशोधन के अभाव में, ट्रिब्यूनल का

मैसर्स ईस्ट इंडिया कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद 142
वीहरियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

आदेश बरकरार नहीं रखा जा सका। हम विद्वान न्यायाधीशों के तर्क और निष्कर्ष से सम्मानजनक सहमत हैं।

हम अपने निष्कर्षों को इस प्रकार सारांशित करते हैं: -

- (1) एचजीएसटी अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (जे) और (1), जिसमें एचजीएसटी अधिनियम, 1973 के नोट 2, नोट 3 के प्रावधान भी शामिल हैं, संविधान और संविधान के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं।

(20) (1991) 83 एसटीसी 276।

संविधान के अनुच्छेद 269(3) और 286(2) के अनुसरण में केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 में तैयार किए गए सिद्धांत। उस सीमा तक 1989 के अधिनियम संख्या 1 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी जाती है।

- (2) एचजीएसटी अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (जे) और (1) के विभिन्न उप-खंडों के दायरे में आने वाले माल का मूल्य कर के दायरे में आता है।
- (3) कर लगाने के उद्देश्य से अंतर-राज्यीय बिक्री एचजीएसटी अधिनियम, 1973 के दायरे से बाहर है।
- (4) ईस्ट इंडिया कॉटन मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा भूरे कपड़े को तैयार कपड़े में बदलने की विशेष गतिविधि तथ्यों और परिस्थितियों में अंतर-राज्यीय बिक्री के बराबर है।
- (5) कर निर्धारण प्राधिकारियों के लिए समग्र कार्य अनुबंध को विभाजित करना और अनुबंध के उस घटक पर कर लगाना खुला है जो एचजीएसटी अधिनियम की धारा 2 के खंड (जे) या खंड (आई) के अन्य उपखंडों में से एक द्वारा कवर किया गया है।, 1973.
- (6) संविधान (छियालीसवें) संशोधन अधिनियम, 1982 द्वारा अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) में बिक्री या खरीद पर अभिव्यक्ति कर की व्यापक परिभाषा के बावजूद, कर केवल केंद्र के मौजूदा प्रावधानों के आधार पर लगाया जा सकता है। बिक्री-कर अधिनियम, 1956, न कि अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के विभिन्न उप-खंडों के आधार पर, जहां तक केंद्रीय बिक्री-कर का संबंध है।
- (7) कर निर्धारण अधिकारी एचजीएसटी अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (जे) या खंड (1) के उप-खंड (ii) के संदर्भ में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह निर्धारित करेंगे कि किस सामान, संपत्ति अनुबंधकर्ता को मिलती है। प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ।

- (8) जब सवाल उठाया जाता है, तो कर अधिकारियों को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह निर्धारित करना होता है कि लेनदेन राज्य के भीतर बिक्री है या अंतर-राज्य बिक्री है।

बिड़ला सीमेंट वर्क्स, कोटकपुरा बनाम पंजाब राज्य और 137 अन्य (ए, एल. बाहरी, जे;)

- (1) एचजीएसटी अधिनियम, 1973 की अनुसूची 'बी' के साथ पढ़ी गई धारा 6 और 15 के तहत बिक्री कर से छूट (शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, उसमें उल्लिखित है) ऐसे सामान के संदर्भ में है। यदि कोई मामला खंड (ii) के किसी भी उप-खंड में आता है तो छूट लागू नहीं होती है।

हम तदनुसार उपरोक्त शर्तों के अनुसार इन याचिकाओं का निपटान करते हैं, और पाटियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

आरएन आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जितेश कुमार शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
झज्जर, हरियाणा

